# ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा



पेजः 4


अगहन संकराईते टुसु हांसे-हांसे आबे गो

रविवारीय, 12 - 18 जनवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-23, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य 2 रूपये

आप सभी प्रिय पाठकों को ग्रीन रिवोल्ट की ओर से मकर संक्रांति, टुसू एवं सोहराई पर्व की हार्दिक शुभकामनायें

### आरपीएफ़ के ए एस आई बालेश्वर प्रसाद को मिला पुरस्कार

**रांची :**दिनांक 08 जनवरी 2020 को रांची स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 01 पर ट्रेन संख्या 15027 हटिया गोरखपुर मौर्य एक्सप्रेस में नूतन कुमारी नामक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हुए असंतुलित हो गई। जिसे रांची आरपीएफ़ पोस्ट के ड्यूटि पर तैनात ए एस आई बालेश्वर प्रसाद ने अपनी जान पर खेलकर महिला को बचाया। बालेश्वर प्रसाद के इस बहादुरी भरे कार्य के कारण उनका सम्मान करते हुए मण्डल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ ने उन्हें 3000 (तीन हज़ार ) की नगद राशि अवार्ड के रूप में दी है।

### इंटरलोकिंग कार्य की वजह से निम्न लिखित ट्रेनें रद्द रहेगी

संवाददाता

**रांची :**उत्तर मध्य रेल्वे के गोविंदपुरी स्टेशन पर नॉन इंटरलोकिंग कार्य की वजह से निम्न लिखित ट्रेनें रद्द रहेगी

ट्रेन संख्या 18102 ( जम्मू तवी - टाटानगर एक्सप्रेस ) दिनांक 14.01.2020 को ( जम्मू तवी से खुलने वाली) रद्द रहेगी ,

वहीं ट्रेन संख्या 18310 ( जम्मू तवी - मूरी - सम्बलपुर एक्सप्रेस )दिनांक 16.01.2020 को ( मूरी से खुलने वाली ) रद्द रहेगी ।

### जंक फ़ूड, बुजुर्गों के आंखों की रौशनी छीन रहा है।

एजेंसियां: ब्रिटिश जर्नल ऑफ ओप्थोमोलॉजी के दिसंबर अंक में छपे एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ है। अमेरिकियों पर किये इस अध्ययन के अनुसार जिन लोगों ने अपने आहार में पश्चिमी भोजन अधिक लिया था, उनकी आंखों में आने वाले विकार की सम्भावना सामान्य से तीन गुना अधिक पायी गयी थी । वैज्ञानिकों ने इसका प्रमुख कारण उनकी आंखों में विकसित होने वाला मैक्यूलर डिजनरेशन नामक विकार को बताया है। यह रेटिना के खराब होने के कारण होता है जोकि देखने की क्षमता को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है। मैक्यूलर डिजनरेशन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन विटामिन, लेजर थेरेपी, दवाओं और आंखों के उपचार से इसे कम किया जा सकता है।इस अध्ययन की प्रमुख लेखक और यूनिवर्सिटी ऑफ बफैलो के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में एसोसिएट प्रोफेसर एमी मिलन ने बताया कि "आप जो खाते हैं वह आपकी आंखों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह तय करता है कि आपकी वृद्धावस्था में आपकी आंखों की रौशनी कैसी होगी।

सिर्फ दो तीन फ्लाइओवरों के बन जाने से ही रांची से जाम की समस्या खत्म हो सकती है, लेकिन दो दशकों में सिर्फ डीपीआर बने

# कब मिलेगी ट्रैफिक जाम से मुक्ति ?

मुख्य संवाददाता

**रांची :** झारखंड राज्य बनने से पूर्व रांची के बाशिंदे ट्रैफिक जाम क्या होता है ? यह नहीं जानते थे। तब जब यहां से छात्र या कामकाजी लोग पटना या किसी अन्य महानगर में जाते थे और वहां ट्रैफिक जाम में कहीं रूकना होता था तो उन्हें यह परेशानी भरा लगता था। रांची लौटने पर यहां के बाशिंदे चैन की सांस लेते थे। लेकिन राज्य बनते ही रांची राजधानी बनी और तेजी से यहां आबादी का बोझ तो बढा ही साथ ही वाहनों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धी हुयी। लेकिन बढती जरूरतों के अनुसार रांची में सड़कों और फ्लाइओवरों का निर्माण नहीं हुआ । यही कारण है कि रांची की सड़के जाम से त्रस्त रहती हैं।

बार -बार यहां फ्लाइओवरों के बनने की बातें तो होती हैं , पर हर बार किसी न किसी कारण से इनका निर्माण रद्द हो जाता है। रांची में अगर पुरानी योजनाओं को खंगाला जाये तो शहर के अंदर फ्लाइओवरों को बनाने का प्लान उसके डीपीआर बनने और फिर कैंसिल होने का रिकार्ड बन जायेगा। कभी मेन रोड में फ्लाइओवर, कभी रातू रोड में, कभी लालपुर में कभी हरमू रोड में फ्लाइओवरों के निर्माण के हवाई प्लान बनते ही रहे हैं, पर ये सब जमीन पर कभी भी नहीं उतर पाये। नतीजा आज भी रांचीवासियों के लिये काम के लिये निकलना किसी दुःस्वप्न से कम नहीं।

## कांटाटोली में दो साल में दो पिलर भी नहीं बना

शहर के सबसे भयंकर जाम वाला क्षेत्र कांटाटोली चौक है। इस चौराहे पर बाहर से भारी वाहन टाटा, हजारीबाग, बंगाल से आते हैं। पास हीं कांटा टोली बस स्टैण्ड भी है। पहले इसी चौराहे पर बस लगाकर यात्रियों को बैठाया जाता था। इससे और भयंकर जाम की स्थिति बनती थी। बाद में प्रशासन की सख्ती के बाद यहां बस लगा कर यात्रियों को बिठाना रूक गया। दो साल पहले कांटा टोली चौक पर फ्लाइओवर बनाने का काम शुरू हुआ। इसके लिये बहुत सारे ताम झाम हुये। पाइप शिफ्ट किये गये, वैकल्पिक मार्ग भी बनाये गये। जमीन का भी अधिग्रहण हुआ। लेकिन दो साल गुजरने के बाद भी आज तक महज दो आधे अधूरे पिलर ही बन पाये हैं और फिलहाल काम रूका हुआ है। इस कारण से कांटा टोली चौक पर अक्सर ही लंबा जाम लगा रहता है। वहीं इस आधे अधूरे निर्माण के कारण सड़क पर और ज्यादा परेशानियां होती हैं।

## रातू रोड की चुनौती

शहर का सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र है रातू रोड। इसी रोड से होकर छत्तीसगढ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर वाहन जाते थे। हालांकि रिंग रोड के बनने से दुसरे राज्यों को जाने वाले भारी वाहनों की आवाजाही रातू रोड से घटी है। लेकिन खुद यहां के बाशिंदे ट्रैफिक जाम से परेशान रहते हैं। कई बार इस रोड में फ्लाइओवर तो कभी एलिवेटेड रोड, तो कभी तीन लेन की सड़क बनाने का प्लान बना लेकिन हर बार किसी मजाक की तरह वह रद्द होते रहा। हाल ये है कि रातू रोड के बाशिंदे चारपहिया वाहन तो अपने घरों में रखते हैं, पर उसे लेकर सड़क पर आने की हिम्मत उनकी नहीं होती। एक बार रांची के विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री तो खुद रातू रोड के ही बाशिंदे हैं ने कहा कि अगर जाम से मुक्ति नही दिला सका तो वोट नहीं मांगेंगे। लेकिन उनका यह प्रण भी झूठा साबित हुआ।

**मानसिक परेशानी और रोडरेज का कारण है ट्रैफिक जाम**

अगर आप रोज भयंकर ट्रैफिक जाम से दो चार होकर आफिस या काम पर आते जाते हैं तो आप अनजाने में मानसिक रोग के शिकार हो रहे हैं। रांची के उन इलाकों के लोग हमेशा खुद को असहज महसूस करते हैं जिनका आना जाना ट्रैफिक जाम से होता है। और यही रोड रेज का कारण भी बनता है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरू शिबु सोरेन को जन्मदिन पर केक खिलाया

## सीसीएल कमांड क्षेत्रों के 120 युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत कैम्पस प्लेसमेंट

रांची :गरीब, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वांगीण विकास के अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए आज 10 जनवरी को सीसीएल दरभंगा हाउस स्थित 'विचार मंच' में 'नियुक्ति पत्र वितरण समारोह' में सीसीएल कमांड क्षेत्र के 120 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। प्लास्टिक इंजीनियरिंग में यह प्रशिक्षण कोल इंडिया एवं सीपेट के मध्य प्रशिक्षण अनुबंध के अंतर्गत आयोजित किया गया जिसमें सीसीएल द्वारा अपने कमांड क्षेत्रों के 120 युवाओं को छः माह के प्रशिक्षण के लिए नामंकित किया गया था। बैच के सभी युवाओं को प्रशिक्षण के उपरांत कैम्पस प्लेसमेंट के माध्यम से देश के विभिन्न प्लास्टिक कंपनियों में रोजगार प्राप्त हुआ जिन्हें आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया । सीसीएल के सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने सभी लाभूकों को नियुक्ति पत्र अपने हाथों से वितरण किया। इस अवसर पर सीपेट, रांची के निदेशक ए.के. राव, सीसीएल सीवीओ ए.के. श्रीवास्वत सहित महाप्रबंधक (सीएसआर) ए.के. सिंह, महाप्रबंधक (एचआरडी) एस.के. सिंह एवं सीपैट वरीय तकनीकी अधिकारी श्री बी. श्रीकर, श्री अभिजित लकड़ा, अभिषेक बख्शी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि सीएमडी सीसीएल गोपाल सिंह ने चयनित प्रशिक्षुओं को नियुक्ति पत्र देते हुए उन्हें बाधाई एवं शुभकामनाएं दी और कहा कि आप जिस भी कंपनी में कार्य करें पूरी तत्परता से करते हुए एक उदाहरण प्रस्तुत करें।

# संगीन आरोप हैं मुख्य कारखाना नीरीक्षक अरूण कुमार मिश्रा पर

संवाददाता

**रांची :** झारखंड औघोगिक क्षेत्र वाला राज्य है। यहां तकरीबन साढे चार हजार छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इन फैक्ट्रियों में कई सुरक्षा के लिहाज से बहुत हीं सावधानी रखे जाने वाली हैं। जिनमें किसी भी किस्म की लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। पिछले ही साल मूरी के हिंडाल्कों में रेड मड के तालाब की चारदिवारी टूट गयी थी और उससे बह कर लाल कीचड़ किसानों के खेत में आ गया था। संयोग की बात रही कि रेलवे लाइन से कुछ मीटर पहले ही यह रूक गया अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

कारखानों में सुरक्षा की सक्षम एजेंसियों से समय समय पर जांच करवाने की जिम्मेदारी मुख्य कारखाना नीरीक्षक की होती है। लेकिन आरोप है कि राज्य के मुख्य कारखाना नीरीक्षक अरूण कुमार मिश्रा इसमें बिल्कुल ही लापरवाह रहे हैं। उल्टे इनपर भ्रष्टाचार के कई संगीन आरोप लगे हैं।

अरूण कुमार मिश्रा पर सबसे गंभीर आरोप है कि इन्होंने अपने चहेते कंपनियों को सारे नियम कानून ताक पर रख कर कारखानों में नीरीक्षण का काम सौंपा। सबसे

कमाल की बात ये है कि इन्होंने जिन कंपनियों के नीरीक्षण करने का लायसेंस रद्द किया उन्हें ही कारखानों में नीरीक्षण का काम भी सौंपा है। ग्रीन रिवोल्ट ने जब इनके भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी एकत्र करनी शुरू की तो कुछ सुत्रों ने ये आरोप भी लगाये कि इन्होंने फर्जी डिग्री वालों को कारखाना नीरीक्षक के तौर पर नियुक्ति दिला दी। इसके अलावा इनकी चहेती कंपनियों ने एक दिन में हीं अलाद्दिन के चिराग के जिन्न की तरह बड़े बड़े फैक्ट्रियों में नीरीक्षण का काम निबटा दिया है। इन्होंने राजभवन को भी अंधेरे में रखकर फर्जी डिग्रीधारियों को फैक्ट्री इंस्पेक्टर की नौकरी दिलवाई है। जब कि डिग्री देने वाले संस्थानों ने खुद यह स्वीकार किया है की उनकी डिग्री फैक्ट्री इंस्पेक्टर जैसे नौकरियों के लिये अमान्य है। कुछ कंपनियों ने आरोप लगाया है कि कारखाना नीरीक्षक अपनी कुछ चहेती कंपनियों को तो नीरीक्षण का काम सौंपते रहे हैं, वहीं जिन्होंने इनके गलत कामों का विरोध किया उसे अरूण कुमार मिश्रा ने परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।उनका लायसेंस रद्द करने से लेकर तरह तरह से परेशान करते रहे हैं।

जानकार बताते हैं कि पूर्व की सरकार में इनकी अच्छी पैठ थी इसक कारण से भी यह आराम से अपने भ्रष्ट कामों को अंजाम देते रहे। ग्रीन रिवोल्ट आगे सबूतों के साथ इनपर लगे आरोपों को सामने लाने का प्रयास करेगा।

# रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से मिले सांसद संजय सेठ

**●चांडिल में ओवरब्रिज को लेकर अविलम्ब सर्वे का मिला आश्वासन पिस्का नगड़ी के ओवरब्रिज की स्वीकृति पर रेलवे बोर्ड को धन्यवाद दिया ●टोरी होकर दिल्ली तक द्रुतगामी ट्रेन चलाने की मांग की**

**रांची :** रांची के सांसद संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव से मुलाकात की। इस दौरान संजय सेठ ने उन्हें नववर्ष की बधाई दी। इसके साथ ही 34 करोड़ की लागत से रांची गुमला मार्ग पर पिस्का नगड़ी रेलवे ओवरब्रिज निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए रेलवे बोर्ड को धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि इस रेलवे ओवरब्रिज के बनने से झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच आने-जाने वाले लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने नागरिकों की तरफ से भी रेलवे बोर्ड को धन्यवाद कहा। मुलाकात के क्रम में सांसद ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को ईचागढ़ के चांडिल में ओवरब्रिज व सड़क की मांग को लेकर दिए गए ज्ञापन पर भी चर्चा की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बोर्ड के चेयरमैन ने अविलम्ब सर्वे कराने व आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। संजय सेठ ने उनसे मांग की कि रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को नगड़ी वाया लोहरदगा-टोरी होते हुए चलाया जाए। इस रेल लाइन का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल जी न किया था। इस लाइन को चालू करना और इसपर द्रुतगामी ट्रेन चलाने का उनका सपना था। चुटिया में भी एक रेलवे ओवरब्रिज की मांग करते हुए उन्होंने किया और आसपास के नागरिकों की समस्याओं से चेयरमैन को अवगत कराया। यह जानकारी सांसद प्रेस प्रतिनिधि संजय पोद्दार ने दी ।

# कुमड़ाबाद में बन रहा झारखण्ड का सबसे लम्बा नदी पुल

दुमका से लौटकर **सिदाम**

**दुमका:** झारखण्ड की उपराजधानी दुमका से करीब 10 किलोमीटर दुरी पर कुमड़ाबाद ग्राम है। पिकनिक स्पॉट के लिए अनुकूल जगह है। मयूराक्षी नदी के किनारे बसे इस गांव में पिकनिक मनाने के लिए लोग प्रायः आते हैं। कुमड़ाबाद में आकर्षण का एक और केंद्रबिंदु बनने जा रहा है। झारखण्ड का सबसे लम्बा नदी पुल यहां बन रहा है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। इस पुल की लम्बाई 2800 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होगी। पुल का एक सिरा मकरमपुर की ओर होगा। वर्तमान में मकरमपुर के आसपास के कई गांव के लोगों को दुमका आने के लिए आसनसोल-चकलताबाद रोड पकड़कर फिर एयरपोर्ट रोड होते हुए दुमका के डीसी चौक तक आना पड़ता है। इस क्रम में 30 किलोमीटर की दुरी तय करना पड़ता है। पुल के तैयार हो जाने से मकरमपुर से दुमका की दुरी 15 किलोमीटर रह जाएगी। फ़िलहाल यहां लोग नाव से आर-पार हो जाते हैं।300 करोड़ के लागत से बन रहे इस पुल का निर्माण राजवीर कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया

जा रहा है। पुल पर ही पार्किंग जोन भी बनेगा। 180 मीटर लम्बा और 8 मीटर चौड़ा बाईपास के रूप में बनाया जाएगा। यहाँ से मयूराक्षी नदी की सुंदरता देखी जा सकती है। नदी का किनारा लोगों को हमेशा आकर्षित करता है। पर आज से 22 साल पहले मयूराक्षी नदी में आई बाढ़ से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। भाग कर स्कूल भवन में शरण लेना पड़ा। आज कुमड़ाबाद गांव के तीन तरफ मयूराक्षी नदी का पानी फैला है। यहां से मकरमपुर की ओर पहाड़ियों का खूबसूरत दृश्य दिखता है। सूरज को डूबते हुए देखना अच्छा लगता है। खूबसूरत दृश्य से आनन्द की अनुभूति देने वाली मयूराक्षी नदी से लोगों की प्यास भी बुझती है। दुमका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति की जाती है। मतस्य विभाग के द्वारा मछली पालन के लिए केजक्लचर की व्यवस्था की गई है। केजक्लचर के तरफ ही पानी में एक विशाल चट्टान डूबा हुआ है। यह चट्टान मेढक की आकृति का है। गर्मी के महीने में जब नदी का जलस्तर कम होता है। वह चट्टान दिखाई देता है। सैलानी उस चट्टान में पिकनिक मनाते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के साथ -साथ कुमड़ाबाद में इतिहास की यादें भी है। अंग्रेजों के जमाने में यह गांव ,बाजार रहमतगंज के नाम से जाना जाता था। यहां नील की खेती होती थी। नील खेती की जमीन नदी के पानी में डूब गया है। प्राचीन हौज के अवशेष आज भी है, जिसमें नील को रखा जाता था और धुप में सुखाया जाता था। उस समय के राजा रघुनन्दन प्रसाद सिंह थे।

उनके महल का अवशेष आज भी है , झाड़ियों के बीच खण्डहर का रूप ले चुका है।महल के पास ही प्राचीन शिव पूजा स्थल भी है जहां राजा पूजा करते थे, उसी परिसर में एक प्राचीन कुआं है। उस स्थल का पुनर्निर्माण किया गया है।वहां लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं। लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में देवी-देवताओं के कई मन्दिर बनाए गए है। मयूराक्षी नदी के किनारे ही श्मशान के पास, एक पुराने पीपल वृक्ष की छाँव पर काली मन्दिर भी है। उस जगह पर शांति की अनुभूति होती है। पुल के बन जाने से ज्यादा से ज्यादा लोग कुमड़ाबाद से जुड़ पाएंगे। प्राकृतिक सुंदरता के साथ- साथ अतीत की बातों को भी जान पाएंगे। ●

## सौंदर्यीकरण से ज्यादा जरूरी है संरक्षण

बड़ा तालाब अब स्वामी विवेकानंद सरोवर का सौंदर्यीकरण का काम एक बार फिर से सवालों के उठने के बाद जोरों पर है। तालाब में पुल से लेकर बीच के टापू पर स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा तक लाइट बत्ती लगा दी गयी है। अस्थायी शौचालय का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन तालाब में जलकुंभी आज भी नासूर बना हुआ है। सालो भर जलकुंभी से पटा रहना ही इस तालाब की नियति है। पाथवे बनाने के नाम पर कंक्रीट का ज्यादा उपयोग और चारो ओर की चारदिवारी इसके पारिस्थितिकी के लिये खतरा भी हैं। जानकारों का कहना है कि तालाब में बरसात के पानी का जाना इस चारदिवारी के कारण कम हो गया है। अब इस तालाब का सौंदर्यीकरण के बाद पर्यटन के लिये उपयोग तो होने लगेगा, पर तालाब का संरक्षण खतरे में पड़ जायेगा। किसी जगह को पर्यटन के लायक विकसित करने में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि उसके संरक्षण में कोई परेशानी न हो। रांची में कमोबेश जितने भी तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ है उनमें ज्यादतर सिर्फ कंक्रीट से पाट दिये गये। सीमेंट से चारो ओर से चारदिवारी और सीढियां बना कर उसे तालाब के बजाय हौदा बना दिया गया। कोकर के डिस्टिलरी पुल तालाब का हश्र हम सब के सामने है। बरियातू के जोड़ा तालाब में भी कंक्रीट के निर्माण के कारण पानी का संचय एकाएक घट गया, चुटिया के ढुमसाटोली तालाब का भी यही अंजाम हुआ।

**रांची में खास तौर पर सौंदर्यीकरण के कारण ही बड़े छोटे बहुत सारे तालाब और डैम बर्बाद हुये हैं। आज रांची की पहचान बड़ा तालाब चर्चा में है। पिछले साल इसमें स्वामी विवेकानंद की विशाल मुर्ति लगा कर करोड़ो खर्च कर इस तालाब का नाम स्वामी विवेकानंद सरोवर रख दिया गया। लेकिन इससे तालाब की सेहत और बिगड़ गयी। चिरकाल से जलकुंभी से भरे रहने वाला बड़ा तालाब की अंदरूनी सेहत आज भी वैसी ही है जैसी पहले थी। बस ऊपरी सौंदर्य पर करोड़ो बहा दिये गये हैं।**

बेहतर होता कि राज्य में कहीं भी किसी रमणिक स्थान के सौंदर्यीकरण और उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने में सरकार पर्यावरण विशेषज्ञों की भी राय ले। जगह को सुंदर बनाने के साथ ही उसका पर्यावरण बचाना भी जरूरी है।

**आस्ट्रेलिया में ज्यादा पानी पीने के कारण दस हजार ऊंटो को गोली मारी जायेगी**

## दस हजार ऊंटों को गोली मार दी जायेगी

आस्ट्रेलियंस के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो पानी के पास ही रहना पसंद करते हैं और कोई भी आम आस्ट्रेलिय अपना आवास पानी के किसी बड़े स्त्रोत से अधिकतम आधे घंटे की दूरी पर ही बनाता है।

पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले विनाशकारी जंगली आग में करोड़ो जानवर जल कर मर गये हैं और अब इसी बीच एक दुखद खबर आ रही है कि वहां 10,000 ऊंटों की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है । कारण बताया जा रहा है कि वे बहुत अधिक पानी पी रहे हैं। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया प्रांत के उत्तर-पश्चिम क्षेत्र के दूरदराज के आबादी वाले आदिवासी अधिकारियों ने कहा कि जंगली जानवर स्थानीय लोगों को खतरे में डाल रहे हैं जो बड़े पैमाने पर सूखे के दौरान पर्याप्त पानी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अधिकारियों ने अब अनंगू पीजंतजतजारा यांकुनितजतजारा (एपीवाई) लैंड्स में ऊंटों को गोली मारने और मारने की योजना बनाई है, उन्होंने सोमवार को एक बयान में कहा कि "ऊंट और अन्य जंगली जानवरों के बहुत बड़े समूह ... एपीपी लैंड में आदिवासी समुदायों पर दबाव डाल रहे हैं।" उन्होंने कहा कि ये जानवर समुदाय के लिए खतरा हैं, उनके दुर्लभ जल और खाद्य आपूर्ति और जीने के लिये अन्य आवश्यक चीजों का उपभोग कर रहे हैं। बयान में कहा गया है, "वर्तमान में चल रही सूखे की परिस्थितियों में बड़े ऊंट मण्डली लोगों और बुनियादी ढाँचे के लिए खतरा है, इस लिये ऊँट नियंत्रण की आवश्यकता है। और इन्हें प्रोफेशनल शूटरों के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण कर गोली मार दी जायेगी।

# किसानों की मायूसी का एक और साल

**देविंदर शर्मा**

एक और साल खत्म हो गया। हालांकि किसानों को अपने बेहतर भविष्य की काफी उम्मीदें थीं, लेकिन अब जबकि 2019 इतिहास का हिस्सा बन गया है, लेकिन कृषक समुदाय अब भी अपनी खेती की लागत को वसूलने के लिए जूझ रहा है। कुछ फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। कृषि संकट के साथ खेत मजदूरों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। कृषि मजदूरी पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गई।

लगभग दो दशक से वास्तविक कृषि आय में गिरावट आई है। यह निराशाजनक प्रवृत्ति 2019 में भी जारी रही। जब देश का लगभग 42 फीसदी हिस्सा अप्रैल में भयंकर सूखे की चपेट में था, तो मुझे लगा कि सूखे के कारण किसानों की दुर्दशा लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक बड़ा मुद्दा बनेगी। लेकिन महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में छिटपुट चर्चा को छोड़कर इस बढ़ते कृषि संकट पर कोई खास राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं हुई थी।

भयंकर सूखे के बाद अनियमित मानसून ने कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर फसलों को बर्बाद किया। इतना ही नहीं, तीन साल के लगातार सूखे के बाद अगस्त में महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। फिर भी वर्ष 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 28.13 करोड़ टन हो गया, जो इससे पहले के पांच वर्षों (2013-14 से 2017-18) के औसत खाद्यान्न उत्पादन से 1.56 करोड़ टन ज्यादा है। हालांकि रिकॉर्ड फसल उत्पादन के युग में भी खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि किसानों को उच्च आय देने में विफल रही। नीति आयोग के अनुसार, पिछले दो वर्षों में वास्तविक कृषि आय में वृद्धि शून्य के करीब रही है। और इससे पहले 2011-12 से 2015-16 के दौरान वास्तविक कृषि आय में वृद्धि प्रति वर्ष आधा फीसदी से भी कम रही।

यह भारतीय कृषि का मजाक है, जो स्पष्ट रूप से खेती की बारहमासी उपेक्षा की ओर इशारा करता है। किसी भी तरह से कृषि को एक गैर-आर्थिक गतिविधि माना जाता है, जिसे किसी तरह सब्सिडी देकर बचाया जा रहा है। प्रमुख आर्थिक सोच का उद्देश्य आबादी के एक बड़े हिस्से को ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में भेजना है, जिसे सस्ते श्रम की आवश्यकता है। ऐसे में कृषि की उपेक्षा त्रुटिपूर्ण अर्थशास्त्र का स्वाभाविक परिणाम है। वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच कृषि में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश जीडीपी का 0.3 से 0.4 फीसदी रहा है, जबकि लगभग 50 फीसदी आबादी खेती में संलग्न है। दुर्भाग्य से जिस बात का एहसास नहीं किया जा रहा है, वह यह कि बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर है और अर्थव्यवस्था में मंदी का दौर चल रहा है। ऐसे में कृषि को मजबूत करना ही ग्रामीण खर्च में बढ़ोतरी का एकमात्र उपाय है, जिससे अधिक मांग पैदा होती है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पहिये को गति देती है। यदि किसान को हर फसल से केवल लाभ हो, तो कृषि क्षेत्र की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अगर खेती एक बार लाभप्रद हो गई, तो शहरों से बेरोजगार युवाओं का बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में लौटकर कृषि कार्य में लग जाएगा। मैंने अक्सर कहा है कि कृषि में भारत की शिथिल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की क्षमता है।

पिछले दो दशकों में कृषि आय में लगातार गिरावट 2017-18 के उपभोक्ता खर्च सर्वे रिपोर्ट में भी उजागर हुई, जिसे सरकार ने दबा दिया। वह रिपोर्ट बताती है कि औसत ग्रामीण परिवार में भोजन पर खर्च प्रतिमाह 580 रुपये है, जो प्रति दिन करीब 19 रुपये बैठता है। इसे 2019 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के निष्कर्षों के साथ देखें, जिसमें 117 देशों में भारत 102 वें स्थान पर है, और सोचें कि 60 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो घटती कृषि आय और घटते घरेलू खाद्य उपभोग के बीच संबंध और भूख के चिंताजनक स्तर को समझना आसान हो जाता है। इसलिए चुनौती ग्रामीण घरेलू उपभोग को बढ़ाना है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र में आय सृजन पर ध्यान केंद्रित करने पर निर्भर करता है। वर्ष 2019 के अंतरिम बजट में किसानों को हुए नुकसान को आंशिक रूप से दूर करने के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने के लिए प्रयास किया गया था, जिसके बारे में मैं वर्षों से कह रहा था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक भूस्वामी किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया था। भले ही इससे किसानों को प्रति माह 500 रुपये का न्यूनतम समर्थन ही मिलता है, लेकिन वास्तव में यह नीतिगत योजना में एक बड़ा बदलाव है, जो कृषि में समर्थन के लिए 'मूल्य नीति' से 'आय नीति' की ओर बढ़ रहा है। मंदी के दौर में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के बजाय, जिसमें 1.45 लाख करोड़ रुपये की कॉरपोरेट टैक्स छूट, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए 75 हजार करोड़ रुपये और रियल एस्टेट को 25,000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज शामिल है, अगर गरीबों के हाथ में और अधिक धन दिया जाए, तो वास्तव में मांग बढ़ सकती है। यह तभी संभव है, जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मनरेगा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये दो ऐसे नीतिगत हस्तक्षेप हैं, जो बदलाव ला सकते हैं।

मेरा सुझाव है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 1.50 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाए, जिससे किसानों को प्रति वर्ष 18,000 रुपये या प्रति माह 1,500 रुपये का प्रत्यक्ष समर्थन मिल सके। इसके अलावा इस योजना को इस तरह विस्तृत करने की जरूरत है, ताकि अनुमानित 40 फीसदी बटाईदार किसान भी इसके दायरे में आ सकें। मनरेगा के लिए भी आवंटन बढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही इसे प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिए, तभी प्रोत्साहन का फायदा उन लोगों को मिल सकेगा, जिन्हें इसकी वास्तव में जरूरत है। इसके साथ कृषि एवं ग्रामीण विकास में कई सुधार करने होंगे, तभी ग्रामीण खर्चों में देश को पुनरुत्थान दिखाई देगा और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कॉरपोरेट जगत टैक्स में कटौती का इंतजार कर सकता है, लेकिन गरीब लोग इंतजार नहीं कर सकते।

# ये जंग अगर यूं ही टल जाये तो अच्छा

यह हमारी विदेश नीति पर एक दुखद टिप्पणी है कि अमेरिका ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के अपने फैसले के बारे में भारत को सूचना देने की जहमत भी नहीं उठाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरानी नेता जनरल सुलेमानी नई दिल्ली में एक आतंकवादी हमले में शामिल थे। वह संभवतः वर्ष 2012 में इस्राइली राजनयिकों पर हुए हमले का जिक्र कर रहे थे। उनके विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी सदस्यों के साथ-साथ जर्मनी और अफगानिस्तान तक से बात की, लेकिन भारत को छोड़ दिया। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को पोम्पियो और ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ को फोन करके दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्रंप को फोन किया।

हमलोगों के विपरीत अमेरिका अब खाड़ी के तेल पर निर्भर नहीं है। वह अपने सहयोगियों-इस्राइल, सऊदी अरब, और खाड़ी के शेखशाही की सुरक्षा के लिए ज्यादा चिंतित है। अमेरिकी नीति इस क्षेत्र की राजनीति को संचालित कर रही है, जो इस क्षेत्र के लिए आपदा हो सकती है। याद कीजिए उस अमेरिकी युद्ध को, जिसने इराक को तबाह करके हमें इस्लामिक स्टेट जैसा आतंकी संगठन दिया। और वह युद्ध इस झूठ पर शुरू किया गया था कि सद्दाम हुसैन के पास परमाणु हथियार थे। ईरान के खिलाफ अमेरिकी युद्ध का ईरान और उस क्षेत्र के लिए, जिसमें भारत भी शामिल है, और भी विनाशकारी परिणाम हो सकता है।

हम अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करते हैं और इसमें से दो तिहाई तेल ईरान के वर्चस्व वाले होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से आता है। इसमें किसी भी तरह के व्यवधान से भारत में अराजकता पैदा होगी, क्योंकि हम अब तक एक महत्वपूर्ण तेल भंडार का निर्माण नहीं कर सके हैं। भारत का रणनीतिक तेल भंडार कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में तीन भूमिगत स्थानों पर है, जिसमें दस दिनों तक खपत के लायक कच्चा तेल है। अतिरिक्त क्षमता के लिए योजना बनी है, पर अब तक निर्माण नहीं हुआ है।

### ईरान अमेरिका युद्ध हुआ तो हमारी अर्थव्यस्था को होगा बड़ा नुकसान

**देश की मीडिया जिस तरह से ईरान और अमेरिका के युद्ध वाली स्थिति पर गैरजिम्मेराराना हरकत कर रही है वह बहुत घातक है। भारतीय टीवी मीडिया ने तो दोनों देशों के सैनिकों असलहों और तैयारियों की तुलना तक कर दी। सोंच कर देखें अगर अमेरिका इरान के बीच युद्ध हुआ तो भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? बदलाव के मुहाने पर खड़ा भारत कितना पीछे चला जायेगा? विपक्ष और विरोधी तो सिर्फ हमलावर होंगे। और मीडिया को सिर्फ मसाला मिलेगा**

खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता की वजह से तेल की कीमतें मौजूदा 60 डॉलर प्रति बैरल से 70 डॉलर प्रति बैरल तक हो सकती हैं और कहने की जरूरत नहीं कि युद्ध की स्थिति में तेल की कीमतें कितनी बढ़ सकती हैं। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा के अनुसार, कीमतों में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से हमारी जीडीपी में 0.2 प्रतिशत की कमी आ सकती है और मुद्रास्फीति में 30 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, अगर रुपये में एक साथ मूल्यह्रास होता है, तो प्रति पांच फीसदी मूल्यह्रास से मुद्रास्फीति में 20 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होगी। संक्षेप में, यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बुरी खबर होगी। भारत को अपने सबसे निकटस्थ स्त्रोत ईरान से तेल आयात करने से रोकने के बाद अमेरिका अब इराक के साथ भी ऐसा करने की राह पर बढ़ सकता है, जो पिछले दो वर्षों में हमारे तेल आयात (20 फीसदी) का सबसे बड़ा स्त्रोत था। ट्रंप ने इराक को धमकी दी है कि अगर उसने इराक स्थित 5,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को वापस जाने के लिए बाध्य किया, तो अमेरिका इराक पर कठोर प्रतिबंध लगा देगा। बेशक सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत जैसे अन्य तेल आपूर्तिकर्ता हैं, लेकिन फारस की खाड़ी की अनिश्चित स्थिति में उन तक पहुंचना एक समस्या हो सकती है।

इसके अलावा एक और कारक है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सऊदी प्रायद्वीप में 70 लाख से ज्यादा भारतीय नागरिक काम करते हैं और सालाना 40 अरब डॉलर अपने देश में भेजते हैं। भारत को यहां दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उस क्षेत्र में युद्ध होने से वहां की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, जिसके चलते भारतीय नागरिकों को अपने आकर्षक रोजगार को छोड़कर देश लौटना पड़ सकता है। इसके अलावा भारत को उन्हें जल्दबाजी में वहां से निकालने के लिए भी मजबूर होना पड़ सकता है, जैसा कि उसे 1990 में कुवैत के इराकी हमले के दौरान दो लाख और 2015 में यमन से छह हजार नागरिकों को निकालना पड़ा था।

प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात तक पहुंच बनाने के लिए इस क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्तिगत प्रयास किए हैं। वह उनके विशाल संप्रभु धन का लाभ उठाना चाहते हैं, जो भारत में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर धन का स्रोत हो सकता है। ये दोनों देश भी अपने तेल से इतर भविष्य के हिस्से के रूप में भारत को देखते हैं और भारत को अपने स्वाभाविक भागीदार के रूप में विकसित होते देखना चाहते हैं। हालांकि युद्ध और संघर्ष उन सपनों की राह में रोड़ा बन सकते हैं। लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंध झेलने के कारण ईरान के पास उस तरह की अतिरिक्त संपत्ति नहीं है और न ही वहां प्रवासी भारतीय हैं। पर उसके पास विशाल तेल एवं गैस भंडार, एक महत्वपूर्ण भूराजनीतिक क्षेत्र, प्रतिभाशाली व शिक्षित आबादी और विशाल बाजार है। वह लंबे समय से भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखता है और उसने अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बनाने के लिए पाकिस्तान की नाकाबंदी को दरकिनार करने के लिए चाबहार बंदरगाह को विकसित करने के लिए भारत को आमंत्रित किया। एक ऐसा समय था, जब ईरानी और भारतीय नीति की समानता ने हमें 1990 के दशक में अफगानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों के समर्थन में सहयोग करने की अनुमति दी थी।लेकिन भारत के लिए ईरान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए एक अनुकूल नीति तैयार करना मुश्किल हो गया है, यहां तक कि अमेरिका भारत पर 'अधिकतम दबाव' भी बनाए हुए है। अब चिंता इस बात की है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध होता है, तो भारत को बिना कुछ हासिल किए कोई पक्ष लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिसके बदले में भारत को केवल दर्द ही मिलेगा।

## बिहार में 33 हजार से अधिक तालाब संवरेंगे

साल 2019 की गर्मियों में बिहार में भीषण जलसंकट की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस संकट की चपेट में राज्य के वे जिले भी आ गये थे, जहां कभी पर्याप्त पानी हुआ करता था। उस वक्त जानकारों ने बताया कि इस जलसंकट की असली वजह तालाबों की उपेक्षा, इनका अतिक्रमण और इन्हें भरा जाना है। सरकार ने अक्तूबर माह के आखिर में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य इन तालाबों को अतिक्रमण से मुक्त कराना और इनका जीर्णोद्धार था। इसके अलावा नये सिरे से तालाबों की खुदाई भी होनी है। राज्य सरकार ने इस अभियान के लिए अगले तीन साल में 24 हजार 524 करोड़ की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। गर्मियों में बिहार के कई उन इलाकों में पानी का घोर संकट छाया रहा, जहां कभी पर्याप्त पानी हुआ करता था, इसकी वजह तालाबों का सूखना और उन पर अवैध कब्जे माना गया, इसलिए सरकार ने एक योजना बनाई है। पिछले दो तीन साल से लगातार गर्मियों में जलसंकट झेल रहे राज्य बिहार में अब सरकार ने तालाबों के संरक्षण का काम शुरू कर दिया है। बिहार सरकार द्वारा इस मकसद से चलाये जा रहे जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य में अब तक एक लाख, 33 हजार, 342 तालाबों की पहचान की गयी है। इस अभियान के तहत पूरे राज्य के स्थानीय प्रशासन द्वारा जो खोजबीन की गयी उसमें अभी तक 1,33,342 तालाबों का पता चला है। इनमें से 13 हजार अतिक्रमण का शिकार बताये जा रहे हैं।

## मूल निवासी ही बचाते हैं जंगल

पुरातन जंगल, दुनिया से लुप्त होते जा रहे हैं। आज भी उनका लगभग एक तिहाई से अधिक हिस्सा उनके मूल निवासियों द्वारा संजो कर रखा गया है। जिनपर भी अब विकास के नाम पर काटे जाने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिसे बचाने के जद्दोजहद सारी दुनिया में जारी है। अभी हाल ही में दावाग्नि ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के जंगलों को लगभग तबाह कर दिया है। जो स्पष्ट तौर पर जंगलों के प्रबंधन में हो रही ढिलाई को दर्शाता है पुरातन जंगलों को बचाये रखने के उद्देश्य से किये गए एक नए अध्ययन से पता चला है कि जंगलों में रहने वाले मूल निवासी आज भी अपने आवास जंगलों को बचाये रखने में सफल रहे हैं।

# प्लास्टिक समस्या: देहरादून से सारा देश सीख सकता है

अनूप नौटियाल

आज के दौर में प्लास्टिक विश्व समुदाय के समक्ष एक बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। कुल प्लास्टिक का एक बड़ा हिस्सा हमारे आसपास एकल प्रयोग (सिंगल यूज) प्लास्टिक के रूप में फैला हुआ है। इससे निपटना संभव है, बशर्ते वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के खिलाफ प्रभावी प्रयास हों। भारत आर्थिक और तकनीकी संपन्न राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार प्रगतिशील है। प्लास्टिक उन्मूलन की दिशा में भी क्रांतिकारी कदम उठाकर यह विश्व के लिए प्रेरणा बन सकता है।

देश में ऐसे कई शहर हैं, जो प्लास्टिक मुक्त अभियान में हिस्सेदारी कर रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ही ऐसे कई संगठन हैं, जो सरकार और समाज के विभिन्न वर्गों के साथ मिलकर यह काम कर रहे हैं। देहरादून में यह काम तीन स्तर पर हो रहा है, सरकारी स्तर पर, सांस्थानिक स्तर पर और नागरिक स्तर पर। सरकारी स्तर पर देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड (डीएससीएल), देहरादून नगर निगम और उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसमें प्रमुख भूमिका में नजर आते हैं। डीएससीएल ने पिछले सितंबर में प्लास्टिक वापसी अभियान चलाया, जिससे सरकारी स्कूलों के 5,200 छात्र-छात्राओं को जोड़ा गया। एक महीने तक चले इस अभियान में छात्रों ने अपने घर और आसपास से 555 किलो प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया, जिसे बाद में रिसाइकल किया गया। देहरादून नगर निगम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में एकल प्रयोग प्लास्टिक मुक्ति को शामिल करने के साथ ही जन जागरूकता अभियान में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। ऐसे ही एक नियामक निकाय के रूप में कार्य करते हुए उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कोई कॉरपोरेट या स्थानीय व्यवसायी पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन न करे। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भी देहरादून को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान में पूरी गंभीरता के साथ संलग्न हैं। आईआईपी ऐसा पहला संस्थान है, जिसके पास प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल कर ईंधन में बदलने की तकनीकी क्षमता है। एक हजार किलो प्लास्टिक कचरे से 800 लीटर डीजल या 700 लीटर पेट्रोल बनाने के संयंत्र के साथ आईआईपी पर्यावरणीय चेतना जागृत करने के मामले में बड़ी भूमिका निभा रहा है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) और कोका कोला ने देहरादून में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को होने वाली क्षति कम करने के लिए एक कार्य योजना शुरू की है।

दून घाटी में कुछ कॉरपोरेट संस्थानों द्वारा भी प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया जा रहा है। फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) की ओर से भी निरंतर खाद्य व्यवसायियों के बीच पर्यावरण संबंधी जागरूकता के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके बेहतर परिणाम भी सामने आए हैं। प्लास्टिक प्रबंधन के क्षेत्र में नागरिक स्तर पर भी विशिष्ट कार्य किया जा रहा है। शहर के कई रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन और नागरिक समूह नियमित रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कार्य कर रहे हैं।

कई नागरिक समूह कूड़े का उसके स्रोत पर ही पृथकीकरण करने, लोगों को कपड़े के बैग वितरित करने और जन जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जैसे काम कर रहे हैं। ये प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2022 तक देश को एकल प्लास्टिक मुक्त बनाने के संकल्प की दिशा में भी उत्साहवर्द्धक संकेत हैं। प्लास्टिक के विरुद्ध ऐसे अभियान देश के दूसरे शहरों में भी हो रहे होंगे। ऐसे प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर हों, तो देश को एकल प्लास्टिक मुक्त बनाना मुश्किल नहीं है।

**लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।**

## फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने चौपट किया भारत का कपड़ा उद्योग

एजेंसियां

भारत के कपड़ा उद्योग की दुनिया भर में धाक थी, लेकिन मुक्त व्यापार समझौतों के बाद दूसरे देशों ने भारत में ही सस्ता कपड़ा भेजना शुरू किया और हम अपनी बादशाहत गंवा बैठे । भारत सरकार का दावा है कि वह अब तक हुए सभी मुक्त व्यापार समझौतों (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एफटीए) की समीक्षा कर रही है। यह तो आने वाले वक्त बताएगा कि समीक्षा में क्या निकलेगा, सिल्क की नगरी कहे जाने वाली भागलपुर पुरैनी गांव में पिछले तीन पीढ़ी से भागलपुरी सिल्क की साड़ी बनाने वाले 62 वर्षीय महमूद बताते हैं कि पिछले एक दशक से बाजार में चाइनीज सिल्क ने हमारे बाजार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। चाइनीज सिल्क से बनी साड़ी भागलपुरी सिल्क के मुकाबले 500 से 600 रुपए सस्ती होती है। इससे हमारे गांव के लगभग हर परिवार की रोजी-रोटी को नुकसान पहुंचा है। कई कारीगर साड़ी बुनने की जगह दूसरे रोजगार करने पर मजबूर हैं। पहले मैं और पूरा परिवार इस काम में दिन रात जुटा रहता था, लेकिन अब काम बहुत कम हो गया है और परिवार के दूसरे सदस्य दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। व्यापारियों ने हमसे सिल्क लेना बंद कर दिया है। केवल सिल्क ही नहीं, बल्कि पूरे कपड़ा (टेक्सटाइल) उद्योग पर एफटीए की मार है। इसके लिए काफी हद तक बांग्लादेश दोषी है। दरअसल भारत ने 2006 में सार्क देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार शुरू किया था। लेकिन कुछ समय बाद चीन ने बांग्लादेश में न केवल अपनी यूनिट लगा ली, बल्कि वहां के माध्यम से भारत में ड्यूटी फ्री फैब्रिक भेजना शुरू कर दिया। कंफेडरेशन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पूर्व प्रधान संजय जैन कहते हैं कि बांग्लादेश से भारत के बीच एफटीए होने के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को बड़ा धक्का लगा है।

# मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया

- मुख्यमंत्री ने झारखंड के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का किया आह्वान
- स्वामी विवेकानन्द के विचार और आदर्श युवाओं में शक्ति एवं ऊर्जा का संचार करता है
- युवा शक्ति से अपनी संपूर्ण ऊर्जा और क्षमता राज्य के नवनिर्माण के कार्यों में लगाएं

**हेमन्त सोरेन, मुख्यमंत्री**

संवाददाता

**रांची :**मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती 'राष्ट्रीय युवा दिवस' के अवसर पर झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता सहित देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने महान दार्शनिक और समाज सुधारक विवेकानंद जयंती के अवसर पर कहा कि स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन को पूरे विश्व में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने झारखंड का नाम भी देश और दुनिया में अंकित करने का काम किया है। उनके विचार और आदर्श युवाओं में शक्ति एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। मुख्यमंत्री ने झारखंड के युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का आह्वान किया। उक्त बातें मुख्यमंत्री ने रांची के विवेकानन्द सरोवर (बड़ा तालाब) स्थित स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहीं।

**राज्य एवं देश की प्रगति युवा शक्ति में निहित**

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारे राज्य एवं देश की प्रगति युवा शक्ति में निहित है। उन्होंने राज्य की युवा शक्ति से अपनी संपूर्ण ऊर्जा और क्षमता राज्य के नवनिर्माण के कार्यों में लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के बल पर झारखंड विकास के पथ पर एक नया आयाम स्थापित कर सकेगा। उन्होंने युवाओं को अपने कार्य क्षमता पर भरोसा रखते हुए निर्भीक होकर किसी भी काम को पूरा करने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वामी जी की संवेदनशीलता, त्याग और समर्पण को जीवन में आत्मसात करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी के आदर्शों पर चलकर ही विकसित समाज का निर्माण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द भारत के महान विभूति थे। उन्होंने देश और दुनिया को मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया।

**उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाय**

इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी के जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानन्द युवाओं के प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द ने ही हमारे देश के समाज में ऊंच-नीच, छुआछूत,भेदभाव के खाई को समाप्त करने का काम किया था। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानन्द जी ने युवाओं को एक संदेश दिया था "उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाय" उन्होंने सभी से स्वामी विवेकानन्द के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने की अपील की। इस अवसर पर पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के सचिव राहुल शर्मा, भवन निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार, रामकृष्ण मिशन आश्रम के स्वामी भवेशानन्द, समाज सेविका श्रीमती महुआ मांझी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल जी तिवारी, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निदेशक अनिल कुमार सिंह, एसडीओ रांची लोकेश मिश्रा सहित बड़ी संख्या में नगरवासी और गणमान्य लोग उपस्थित थे।

### बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आंचल शिशु आश्रम पहुंचे और बच्चों के साथ कुछ समय बिताया

## झालदा स्टेशन पर दो एटीवीएम मशीन लगा

संवाददाता

रांची :मण्डल के झालदा स्टेशन पर दो ATVM मशीन लगाया गया। इससे संबन्धित एक जागरूकता अभियान भी चलाया गया । इस क्षेत्र के माननीय सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो एवं माननीय विधायक नेपाल महता ने भी इसे लगाने की मांग की थी।

इसके अंतर्गत स्टेशन में मौजूद यात्रियों को अनारक्षित रेल टिकट एप को मोबाइल पर प्रयोग करने की जानकारी दी गई एवं उसके लाभ के बारे में भी बताया गया। साथ ही एटीवीएम मशीन के प्रयोग एवं लाभ के विषय में भी बताया गया। इन दोनों के ही उपयोग से यात्री लंबी लाइन में लगने से बच सकेंगे इससे समय की बचत होगी। साथ ही स्वयं अपना टिकट काट सकेंगे। एटीवीएम से टिकट लेने हेतु स्मार्ट कार्ड बनाना होता है और उसे रिचार्ज कर टिकट लिया जा सकता है। जिनके पास स्मार्ट कार्ड नहीं होता है वह एटीवीएम फैसिलेटर के द्वारा टिकट ले सकता है। एटीवीएम फैसिलेटर नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। मण्डल के रांची , हटिया, मूरी,लोहरदगा आदि स्टेशनों पर यह सुविधा पहले से जारी है। यहाँ यात्रियों के लिए मासिक सीजन टिकट की सुविधा भी उपलब्ध है। इस मौके पर वाणिज्य निरीक्षक सुखदेव रक्षित वाणिज्य निरीक्षक उग्रसेन कुमार , आरक्षण पर्यवेक्षक अनिल कुमार सिंह इत्यादि उपस्थित थे।

**माननीया राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने न्यायाधीश एल.पी.एन शाहदेव की पुण्यतिथि पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजली दी।**

# 17 - 19 जनवरी तक जनजातीय दर्शन पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार

संवाददाता

- दुनिया में पहली बार ट्राइबल फिलॉसफी पर हो रहा अंतरराष्ट्रीय सेमिनार
- उद्घाटन समारोह में राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे शामिल, समापन समारोह में मौजूद रहेंगे जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा
- रांची के आड्रे हाउस में तीन दिनों तक चलने वाले सेमिनार में विदेशों से 12 और देश के 100 से ज्यादा विद्वान करेंगे शिरकत

**रांची :**17 से 19 जनवरी तक जनजातीय दर्शन (ट्राइबल फिलॉसफी) पर अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन होगा। डॉ रामदयाल मुंडा ट्राइबल वेलफेयर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रांची की ओर से इस अंतरराष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। 17 जनवरी को सुबह दस बजे उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी। संस्थान के निदेशक रणेंद्र कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। दुनिया में पहली बार ट्राइबल फिलॉसफी पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हो रहा है। इस सेमिनार में ट्राइबल फिलॉसफी से जुड़े 12 अंतर्राष्ट्रीय विद्वान और देशभर से100 से ज्यादा विद्वान शामिल होंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों में आदिवासी दर्शन से जुड़े प्राध्यापक, शोधकर्ता और विद्यार्थी की भी भागीदारी होगी। इसके अलावा राज्य में 32 जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

**तीन दिनों में होंगे 12 एकेडमिक सेशन**

3 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में उद्घाटन और समापन सत्र को छोड़कर 12 एकेडमिक सेशन होंगे. हर सेशन में ट्राइबल कल्चर के अलग-अलग आयामों पर विद्वान अपना प्रेजेंटेशन देंगे. इस दौरान आदिवासियों के रहन-सहन, खान-पान, दिनचर्या और कला-संस्कृति समेत अन्य मुद्दों पर बातें होंगी। सेमिनार का मकसद ट्राइबल फिलॉसफी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करना है।

**नेतरहाट में जुटेंगे जनजातीय और लोक चित्रकला के कलाकार**

इस मौके पर बताया गया कि संस्थान के द्वारा नेतरहाट में 10 से 15 फरवरी तक जनजातीय और लोक चित्रकला पर कार्यक्रम का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में झारखंड समेत देश के विभिन्न इलाकों से जनजातीय व लोक कला के कलाकार शामिल होंगे. उनके चित्रों की पेंटिंग भी यहां देखने को मिलेगी।

संवाददाता सम्मेलन में आयोजन समिति के अध्यक्ष व डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सत्यनारायण मुंडा, लेखक महादेव टोप्पो, रांची यूनिवर्सिटी के टीआरएल डिपार्टमेंट के प्राध्यापक प्रो हरि उरांव, दामोदर सिंकू, दुंबे दिग्गी, श्रीमती शांति खलखो, व अन्य मौजूद थे।

# धान अधिप्राप्ति को लेकर उपायुक्त ने दिये आवश्यक दिशा-निर्देश

संवाददाता

देवघरः उपायुक्त श्रीमती नैंसी सहाय की अध्यक्षता में धान अधिप्राप्ति को लेकर समाहरणालय सभागर में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपयुक्त द्वारा राज्य से प्राप्त निर्देशो के आलोक में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर किसानों से धान अधिप्राप्ति एवं उन्हें निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के हिसाब से राशि के भुगतान को लेकर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया। इसके अलावे उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गयी कि सभी प्रखंडों में पैक्स का चयन किया जा चुका है। देवघर में गोपालपुर, मधुपर में गा-ड़िया, सारठ मेंसबेजोर, ठाड़ी, सारवां मेंरक्ति, करौं में बघनाड-ीह, मोहनपुर में बलथर, सरासनी पालाजोरी में कांके, देवीपुर में अमडीहा, मारगोमुण्डा में पिपरा, एवं सोनारायठाड़ी में बिंझा पैक्स का चयन किया गया एवं सभी को मिल के साथ टैग कर दिया गया है। ऐसे में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को उन्होंने निदेशित किया कि सभी पैक्स को संचालित करने हेतु विधिवत बैठक कर इसे सुनिश्चित कर लें। बैठक के दौरान उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेशित किया कि जल्द से जल्द पैक्स वाइज जनसेवक एवं कंप्यूटर ऑपरेटर को टैग करें। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि धान अधिप्राप्ति हेतु 2000 रुपये, क्विंटल (1815 रुपये समर्थन मूल्य 185 रुपया बोनस) राज्य सरकार द्वारा तय किया गया है। ऐसे में उपायुक्त ने सभी सभी संबंधित अधिकारियों को निदेशित किया कि किसानों को पैक्स में धान देने हेतु जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक धान की अधिप्राप्ति हो सके।

## एसआई बलराम कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, यू.के.विश्वास पुरस्कृत

संवाददाता

रांची : 08 जनवरी 2020 को हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 01 पर ट्रेन संख्या 18452 तपस्विनी एक्सप्रेस से चलती ट्रेन में उतरते हुए एक पुरुष यात्री नासिर खान रेलवे लाईन के बीच गिरकर जख्मी हो गए और उनके दोनों पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। यह घटना होते ही पोस्ट कमांडर श्री ए.के.सिंह ,एसआई सूरज पांडे , एसआई बलराम कुमार, कांस्टेबल नरेंद्र कुमार, यू.के.विश्वास ने उन्हें तुरंत रेलवे हॉस्पिटल इलाज के लिए ले गए। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए आदरणीय मण्डल रेल प्रबन्धक नीरज अंबष्ठ ने उन्हें 4000 (चार हज़ार ) की नगद राशि ग्रुप अवार्ड के रूप में देकर पुरस्कृत किया है ।

## छात्र क्लब ग्रुप ने किया सम्मानित

**रांची :**छात्र क्लब ग्रुप ने मोबाइल चोर को दौड़ा कर दबोचने पर बहादुरी के लिये आकाश कुमार को सम्मानित किया। आकाश कुमार ने पिस्का मोड़ में मोबाइल छिन कर भाग रहे उचक्के को धर दबोचा था। छात्र क्लब ग्रुप की ओर से शिवकुमार शर्मा, जगदेव मिस्त्री और संतोष प्रसाद ने आकाश कुमार को माला पहनाया और लड्डू खिला कर सम्मानित किया।

# जलवायु परिवर्तन पर हर पल करना होगा काम

राजन कुमार

**पिछले दिनों** पटना में मंत्रियों अफसरों की एक बैठक हुई और सबने एक स्वर में कहा कि जलवायु परिवर्तन वर्तमान में सबसे बड़ा संकट है। इसके कारण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना बिहार जैसे राज्य को करना पड़ रहा है। इन आपदाओं से मुक्ति पाने के लिए हमें जल-जीवन-हरियाली अभियान की महत्ता को समझना होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। विकास के काम तो किये ही जा रहे हैं और किये जाते भी रहेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर हर पल काम करते रहना होगा।'ये बातें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहीं। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के ज्ञान भवन में सोमवार को जल-जीवन-हरियाली अभियान यात्रा के क्रम में पटना प्रमंडल की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स पटना आये थे और उन्हें जलवायु परिवर्तन के लिए किये जा रहे कामों के बारे में जानकारी दी गई थी। यहां से जाने के बाद उन्होंने बिहार में क्लाइमेट चेंज पर किये जा रहे कामों की तारीफ भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जनवरी 2020 को दिन के 11.30 बजे से 12 बजे तक पुरुष, महिला, युवा सभी को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए आप सब प्रेरित करें। 16 हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी मानव श्रृंखला बनाने का लक्ष्य रखा गया है, आप सब इसमें जरुर शामिल हों। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव को लेकर 13 जुलाई को सभी दलों के विधायकों एवं विधान पार्षदों की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें जल-जीवन-हरियाली अभियान को मिशन मोड में चलाने का निर्णय लिया गया। आज जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जो योजनाएं चलायी जा रही हैं, उन पर भी समीक्षा बैठक में चर्चा हुई। जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने अनुभव साझा किये, उसका भी जवाब अधिकारियों द्वारा दिया गया। कुछ लिखित रूप में भी बातें आयी हैं, जो संबद्ध विभागों को भेज दी जाएगी। सात निश्चय के अंतर्गत चलायी जा रही योजनाओं के प्रगति के बारे में भी जानाकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत 11 अवयव हैं, इस पर तीन वर्षों में 24 हजार 524 करोड़ रुपए खर्च किये जायेंगे। जरूरत के अनुसार और राशि में वृद्धि भी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत राज्य स्तर पर परामर्शदातृ समिति और जिला स्तर पर जिला परामर्शदातृ समिति का गठन किया गया है। अपने-अपने इलाके में सभी जनप्रतिनिधि इसके लिए लोगों को जागरुक करें। पांच प्रमंडलों की समीक्षा बैठक की जा चुकी है। लोगों में जागृति लाने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान यात्रा के अंतर्गत जागरुकता सम्मेलन कर रहे हैं। सार्वजनिक आहर, पईन, पोखरों का अतिक्रमणमुक्त कराना और उसका जीर्णोद्धार कराकर जल संचयन का काम किया जाएगा। उससे भूजल स्तर भी बरकरार रखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र के ज्ञान भवन में पटना प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक के अंतर्गत पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर, बक्सर एवं रोहतास जिले की जल-जीवन-हरियाली अभियान से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक में सार्वजनिक कुओं, चापाकल, आहर, पईन का जीर्णोद्धार, नलकूपों, कुओं एवं चापाकल के किनारे सोख्ता निर्माण, जल संरक्षण संरचना, छोटी-छोटी नदियों, नालों, पहाड़ी क्षेत्रों में चेकडैम एवं जल संचयन के अन्य संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्त्रेतों का सृजन, सरकारी भवनों में छत वष जल संचयन, पौधशाला सृजन एवं सघन वृक्षारोपण, जैविक खेती एवं टपकन सिंचाई, सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहन एवं ऊर्जा की बचत, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नालियां, राज्य में बचे सभी संपर्क विहीन बस-ावटों को पक्की सड़कों से जोड़ना, शौचालय निर्माण घर का सम्मान, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जर्जर तारों का बदलाव, पावर सब स्टेशन के निर्माण से संबंधित जानकारी दी गई। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं एवं शिकायतों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। संबंधित विभाग के अधिकारियों ने उसके संबंध में भी अपनी बातें रखीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।उन्होंने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण वषपात में कमी हो रही है। कभी सूखे की स्थिति तो कभी बाढ़ की स्थिति बन रही है। आपदा प्रभावित लोगों को तो हमलोग मदद कर ही रहे हैं लेकिन इन सभी चीजों से मुक्ति पाने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान की महत्ता को समझना होगा। आने वाली पीढ़ी के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। विकास के काम तो किये ही जा रहे हैं, किये जाते भी रहेंगे, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर हर पल काम करते रहना होगा।

इस बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कृषि मंत्री प्रेम कुमार, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि, उद्योग मंत्री श्याम रजक, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार, पटना प्रमंडल के सांसद, मुख्य सचिव दीपक कुमार, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पाण्डेय, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, अन्य विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, योजना एवं विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

### बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने कहा कि 19 जनवरी 2020 को दिन के 11.30 बजे से 12 बजे तक पुरुष, महिला, युवा सभी को मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए आप सब प्रेरित करें।

## किसानों का जमीन समाधि सत्याग्रह, फिलहाल स्थगित

एजेंसियां

जयपुर विकास प्राधिकरण की नींदड़ आवासीय योजना के भूमि अधिग्रहण और दिए जा रहे मुआवजे के विरोध में नींदड़ के किसानों का सत्याग्रह शुक्रवार को स्थगित हो गया है। किसानों की मांग है कि अधिग्रहित जमीन का मुआवजा भूमि अधिग्रहण कानून 2014 के हिसाब से दिया जाए। इसी मांग को लेकर किसान चार दिन से भूमि सत्याग्रह कर रहे थे।

शुक्रवार को किसानों से मिलने गए मुख्य सचेतक और कांग्रेस नेता महेश जोशी ने सरकार की ओर से किसानों को आश्वासन दिया कि इस समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, नींदड़ बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक और आंदोलन के अगुआ नगेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि महेश जोशी के वादे के बाद फिलहाल भूमि सत्याग्रह स्थगित कर दिया है। जोशी ने किसानों से वादा किया है कि जब तक समस्या का कोई हल नहीं निकलता तब तक नींदड़ में जयपुर विकास प्राधिकरण धरना स्थल और नींदड़ की जमीन पर कोई कब्जा नहीं लेगा। बनने वाली कमेटी में जेडीसी, खुद महेश जोशी और किसान शामिल होंगे। उम्मीद है अब कोई रास्ता निकल आएगा। अगर कमेटी में भी हमारी मांगें नहीं मानी गईं तो हम फिर से आंदोलन करेंगे।

# फोटो न्यूज

रांची विश्वविद्यालय के मोराबादी स्थित बेसिक साइंस कैंपस में पेड़ का संदेश। वर्तमान में जूलॉली के प्राध्यापक डॉ. आनंद कुमार ठाकुर, वीसी डॉ. रमेश कुमार पांडेय, साइंस डीन डॉ. अशोक कुमार चौधरी एवं सभी प्राध्यापकों के प्रयास से पूरा कैंपस एक खुबसूरत बगीचे सा दिखता है।

# अगहन सांकराईते टुसु हांसे हांसे आबे गो

देवाशीष

*कथा बतायी जाती है कि , एक ग्रामीण चरकू महतो की सुंदर पुत्री थी उसका नाम टुसू था। उसकी सुंदरता की दूर - दूर तक चर्चा थी। जिसे सुन कर वहां के राजा को जलन होने लगी। राजा का मानना था कि सुंदर स्त्रियां सिर्फ राजघरानों में ही होती हैं। इसी जलन में राजा ने दुष्टता करते हुये चरकू महतो की पुत्री टुसू से जबरन विवाह करना चाहा। इससे सारे ग्रामीण आक्रोशित हो गये और राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। राजा की सेना और टुसू के गांव वालों के बीच घोर युद्ध हुआ। टुसू ने अपने पिता और गांव वालों को राजा की सेना से हारता देख नदी में जलसमाधि ले ली। इसे देखते ही ग्रामीण और राजा की सेना हतप्रभ रह गये और युद्ध वहीं रूक गया। लेकिन राजा को इस बात की बहुत ग्लानि भी हुयी। उसने क्षमा मांग कर वह पूरा इलाका टुसू के पिता को सौंप दिया और चला गया। इसके बाद से ही टुसू के सम्मान में यह पर्व मनाया जाने लगा।*



आज टुसू पर्व झारखंड में पंच परगना क्षेत्र का महत्वपूर्ण पर्व है। यह जाड़ों में फसल कटने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। टूसू का शाब्दिक अर्थ कुँवारी है। इस पर्व के इतिहास का या कुछ खास लिखित स्त्रोत नहीं है लेकिन यह अत्यंत ही रंगीन और जीवन से परिपूर्ण त्यौहार है। मकर संक्राति के अवसर पर मनाये जाने वाले इस त्यौहार के दिन पूरे कूड़मी एवं आदिवासी समुदाय द्वारा अपने नाच-गानों एवं मकरसंक्रांति पर सुबह नदी में स्नान कर उगते सूरज की अर्घ/प्रार्थना करके टुसू(लक्ष्मी/सरस्वती) की पूजा की जाती है तथा नववर्ष की समृद्धि और खु-शहाली की कामना की जाती है इस प्रकार यह आस्था का पर्व श्रद्धा,भक्ति और आनंद से परिपूर्ण कर देती हैं।

टुसु मुख्यतः तीन नामों से जाना जाता है। **टुसु परब, मकर परब, पूस परब** । इन तीन नामों के अलावा बांउड़ी एवं आखाईन जातरा का एक विशेष महत्त्व है। बांऊड़ी के दूसरा दिन या मकर सक्रान्ति के दूसरे दिन "आखाईन जतरा" मनाया जाता है। कृषि कार्य समापन के साथ -साथ कृषि कार्य प्रारंभ का भी आगाज किया जाता है। यानि कि बांउड़ी तक प्रायः खलिहान का कार्य समाप्त कर आखाईन जतरा के दिन कृषि कार्य का प्रारंभ मकर संक्रांति के दिन होता है नये वर्ष में अच्छे राशि गुण (पांजी अनुसार) वाले घर के सदस्य के द्वारा सुबह नहा धोकर नये कपड़े पहनकर उगते सूर्य की पहली किरण पर हारघुरा (जोतना) यानी (बोहनी)हाईल पून्हा नेग संपन्न करता है खेत में हार तीन या पांच या सात बार घुमाकर बैलों को हार जुआईट के साथ घर लाकर आंगन में दोनों बैलों के पैरों को धोकर उनके पैरों पर तेल लगाया जाता है उसके बाद हल जोतने गये कृषक गोबरडिंग(बहूत सारा गोबर रखने की जगह) में गोबर काटकर कृषि काम की शुरूआत करता है। कृषक के घर घुसने के पहले उसके पैर को धोकर तेल लगाया जाता है उसके उपरांत घर के सभी पुरुष सदस्यों का पैर धोकर तेल लगाया जाता है। यह काम घर की मां या बड़ी बहु करती है। इस प्रकार यह दिन कुड़मी एवं आदिवासी जनजातीय समुदायों, किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है। आखाईन जतरा के दिन हर तरह के काम के लिए शुभ माना जाता है। बड़े बुजुर्ग के कथानुसार इस दिन नया घर बनाने के लिए नीव खोदना या शुरू करना अति उत्तम दिन माना जाता है। इसमें कोई पोथी का जरूरत नहीं पड़ती है इस दिन को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस टुसू परब में "पीठा" का भी एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। आखाईन जतरा के बाद से ही फाल्गुन महीना तक सगे समबन्धि,रिश्तेदारों के घर"गुड़ पीठा"पहुँचाया जाता है। गुड़ पीठा पहुँचाने की इस नेग (रिवाज,प्रथा)को "कुटुमारी"कहा जाता है। गुड़ पीठा प्रायः तीन तरह का बनाया जाता है।ः 1.थापा पीठा( आबगा गुड़ पीठा) 2.गरहोवआ पीठा (जल दिया पीठा/गुला पीठा) 3.मसला पीठा ।

यह त्यौहार झारखंड के दक्षिण पूर्व रांची,खूंटी, सरायकेला-खरसावां,पूर्वी सिंहभूम,पश्चिम सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिलों ,तथा पंचपरगना क्षेत्र का प्रमुख पर्व है,टुसू पर्व पंचपरगना की सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसकी शुरुआत 15 दिसंबर यानी अगहन संक्रांति से शुरू होती है। अगहन संक्रांति को कुंवारी कन्याओं द्वारा टुसु(चौड़ल) की स्थापना (थापने) की जाती है। टुसू को लक्ष्मी/सरस्वती के प्रतीक के रूप में एक कन्या माना गया है जिसकी कुंवारी कन्या पूरे एक महीना सेवा (पूजा प्रार्थना) करती है। पूरे पौस मास तक टूसू मेला का आयोजन हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस तरह के मेलों का आयोजन किसी अन्य पर्व - त्यौहारों में कभी नहीं होती। भारत की प्रसिद्ध कुंभ मेला के अलावे टूसू पर्व ही एक ऐसा पर्व है जो पूरे दो महीने तक लगातार अलग-अलग जगहों पर विशेष कर नदी के किनारों,टुंगरी,पहाड़ो,धार्मिक स्थलों पर विशेष रुप से टूसू पर्व का आयोजन होता है इससे प्रतीत होता है कि टुसू मेला का कितना महत्व है।

आज यह पर्व संपूर्ण पंचपरगना ही नही समूचा झारखंड का प्रमुख त्यौहार है जिसको मानने वाले झारखंड के सभी जातियों समुदायों के लोग आपस में मिलजुलकर पुरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह पर्व झारखंड की संस्कृति का पोषक स्वरूप है जिसमें पुस गीत,नृत्य,वाद्य यंत्रों की मधुर संगीत है। इसमें एक विशेष प्रकार की रस्म है,एक विशेष प्रकार की मान्यता है। इसमें ही नये वस्त्र पहने का विशेष महत्व है। पि-रवार के सभी लोगों के लिए नये कपड़े लेने का रिवाज है। इस प्रकार यह पर्व धार्मिक विश्वास,पारंपरिक मान्यता,नये वर्ष के आगमन, अच्छे फसल की प्राप्ति और खुशहाली के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ●

## उपन्यास के नाम को लेकर मैं बहुत पर्फेक्शनिस्ट हूँः महुआ माज़ी

**●दिल्ली पुस्तक मेला में महुआ माजी ने किया अपने नए उपन्यास से अंश पाठ**

दिल्ली में चल रहा किताबों का सबसे बड़ा मेला- विश्व पुस्तक मेला में पाठकों की भागीदारी देखने लायक है। इस मेले में पाठकों के बीच लेखिका महुमा माजी ने अपने शीघ्र प्रकाश्य उपन्यास से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ कर सुनाया। महुआ के दो उपन्यास 'मैं बोरिशाइल्ला' और 'मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ' राजकमल प्रकाशन से पहले से प्रकाशित हो चुके है। मेले में पाठक इन किताबों को पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं।

लेखक से मिलिए कार्यक्रम में लेखक-आलोचक प्रभात रंजन और मृत्युंजय के उपन्यास के नाम को लेकर किए गए सवाल का जवाब देते हुए महुआ ने कहा, ''उपन्यास के नाम को लेकर अक्सर मुझसे सवाल पूछे जाता है, लेकिन मैं बहुत पर्फेक्शनिस्ट हूँ। जब तक उपन्यास पूरा न हो जाए नाम तय कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है।''महुआ के नए उपन्यास का पाठक बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। भाषा और शिल्प में अपने लोक को समाहित करने वाली लेखिका हमेशा अपने उपन्यासो में नए विषयों को लेकर आती हैं।

## सुधा रमण और योगेश सिंह ने जिंदा किया ओट्टेरी झील

**एजेंसियां** :कुछ साल पहले तक, चेन्नई के वंडलूर चिड़ियाघर की ओट्टेरी झील पर सर्दियों के मौसम में हज़ारों पक्षी आते थे। आर्कटिक सर्किल की ठंडी जगहों से आनेवाले इन विदेशी पक्षियों के लिए यह झील सर्दी के मौसम में उनका घर हुआ करती थी। लेकिन पिछले कुछ समय से, सर्दियों में यहां आने वाले इन पक्षियों की संख्या कम होती गयी क्योंकि यह झील मरने की कगार पर थी। साल 2016 में आये वरदा सायक्लोन और फिर हर साल गर्मियों में लगातार पड़ने वाले सूखे से प्रभावित झील मानों बिल्कुल सूख गयी थी। पिछले साल के सूखे ने रही-सही कसर भी पूरी कर दी। इससे न सिर्फ झील बल्कि चिड़ियाघर की हालत भी बिल्कुल खराब हो गयी और अधिकारियों को यहां के जीव-जन्तुओं को बचाने के लिए बाहर से पानी मंगवाना पड़ा। पिछले साल तक यहां इन पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया था।

**झील को बचाने की पहल**

बारिश के पानी से रिचार्ज होने वाली यह झील 18 एकड़ में फैली हुई है और चंद जगहों को छोड़कर यह पूरी तरह से सूख गयी थी। वंडलूर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित इस झील को लगातार रिचार्ज की ज़रूरत होती है। पर पिछले कई सालों से पड़ रहे सूखे की वजह से यह मुमकिन नहीं हो पा रहा है। पर कहते हैं न, 'जहां चाह, वहां राह' इस बात पर विश्वास रखने वाली कर अफसर सुधा रमन ने इस स्थिति से लड़ने की ठानी। सुधा, वंडलूर चिड़ियाघर की डिप्टी डायरेक्टर हैं। उन्होंने डायरेक्टर योगेश सिंह के मार्गदर्शन में ओट्टेरी झील को एक नई ज़िन्दगी दी। उन्होंने अपना काम फरवरी 2019 से शुरू किया और आठ महीने बाद, अक्टूबर 2019 में यह झील पानी से भरी हुई थी। सुधा ने इस बारे में बताया, ''सबसे पहला काम प्राकृतिक ड्रेनेज चैनल को साफ़ करना था और इसके बाद गाद निकाली गयी। इस मिट्टी का प्रयोग झील में टीले बनाने के लिए किया और फिर यहाँ पर हमने ऐसे पेड़-पौधे लगाये जो कि पक्षियों को अपनी तरफ आकर्षित करें। इन टीलों पर मैंग्रोव, अर्जुन, जामुन, गुलर जैसे पेड़ लगाये गये, जिन्हें बारिश के पानी से पोषण मिला। हम खुद हैरान थे कि इस बार ये सभी टीले बरसात के मौसम में पानी में डूब गये थे और सभी पेड़ हरे-भरे हो गये। आज झील फिर से जीवित हो चुकी है और पक्षियों का फिर से आना शुरू हो गया है।

## ऑक्सीजन सिलेंडर

# पर्यावरण की मदद है भोजन और अन्न की बर्बादी रोकना

शशिभूषण

भोजन की बर्बादी कमोबेश हर देश में होती है। यहां तक कि विकसित देशों (अमेरिका अव्वल) में अन्न की बर्बादी छोटे मुल्कों के मुकाबले कहीं ज्यादा होती है। शायद भोजन की महत्ता को समझते हुए सऊदी अरब में बचा खाना फेंकने की आदत के विरोध में लोग एकजुट हो रहे हैं। अब लोग ऐसी थाली और तरीका अमल में ला रहे हैं, जिससे परोसा हुआ खाना ज्यादा दिखाई दे। दरअसल, सऊदी में ज्यादा खाना परोसना अच्छी मेहमान नवाजी और संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। इसके लिए थाली में चावल का टीला सा खड़ा कर दिया जाता है। लोग थाली के दोनों ओर से चावल खा लेते हैं, पर बमुश्किल ही बीच तक पहुंच पाते हैं। बाकी खाना नहीं खा पाते, जो बाद में कूड़े में फेंक दिया जाता है। लेकिन अन्न की बर्बादी इस तस्वीर का एक पहलू है। भोजन को बर्बाद होने से बचाकर पर्यावरण को बेहतर बनाया जा सकता है किंतु इससे अधिकांश लोग अनभिज्ञ हैं। भोजन का फेंका जाना पहली निगाह में भले ही मामूली सी बात प्रतीत हो या फिर एक बड़े कार्यक्रम की अपरिहार्यता बता कर इससे पल्ला झाड़ लिया जाए, लेकिन यह एक गंभीर समस्या है जिसकी प्रकृति विश्वव्यापी है।

इस संदर्भ में विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट में खाद्यान्नों की बर्बादी से जुड़ी चुनौतियों का बारीकी से विश्लेषण किया गया है। संगठन द्वारा प्रस्तुत-खाद्य अपव्यय पदचिह्नः प्राकृतिक संसाधनों पर प्रभाव वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य अपव्यय को रोके बिना खाद्य सुरक्षा सम्भव नहीं है। इस रिपोर्ट में खाद्य अपव्यय का अध्ययन पर्यावरणीय दृष्टिकोण से करते हुए बताया है कि भोजन के अपव्यय से जल, जमीन और जलवायु के साथ साथ जैव-विविधता पर भी बेहद नकारात्मक असर पड़ता है। हर साल 1.3 अरब टन खाना बर्बाद हो जाता है। इस बर्बाद खाने का अधिकतर हिस्सा कचरे के बड़े ढेरों में पहुंच जाता है और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देने लगता है। खाने का बर्बाद होना इंसानों के लिए आज सबसे बड़ी समस्या है। हमारे ग्रह पर लगभग 90 अरब लोग किसी न किसी तरह खाद्य संकट से जूझ रहे हैं और लगभग 82 करोड़ लोगों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया में तैयार किए जाने वाले खाने का एक तिहाई हिस्सा बर्बाद चला जाता है। खाने की बर्बादी का मतलब सिर्फ खाना बर्बाद होना ही नहीं है। यह पैसों, पानी, ऊर्जा, जमीन और परिवहन साधनों की भी बर्बादी है।

अपने खाने को यूं ही छोड़ने का मतलब है जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना। छोड़ दिया गया खाना आमतौर पर लैंडफिल यानी कचरे के ढेरों को भेज दिया जाता है। वहां ये सड़ता है और मीथेन गैस पैदा करता है। पूरी दुनिया में बर्बाद हुए खाने से पैदा होने वाली ''ग्रीनहाउस गैसों' की तुलना देशों से की जाए तो यह अमेरिका और चीन के बाद सबसे ज्यादा ऐसी गैसें पैदा करता है। ''ग्रीनहाउस गैस' वातावरण को किस कदर प्रदूषित या नुकसान पहुंचाते हैं, यह तय किसी से छुपा नहीं है। हाल के वर्षो में पर्यावरण की शुद्धता या कहें प्रदूषण को लेकर हाय-तौबा मची हुई है। यहां तक कि अभी पिछले हफ्ते ही मैड्रिड में पर्यावरण की चिंता में जार-जार हो रहे करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। यानी पर्यावरण को लेकर धनी देश कितने गैरजिम्मेदार हैं, यह जगजाहिर है।

ताजा अध्ययन बताते हैं कि भोजन और खाद्य सामग्री की बर्बादी का सीधा मतलब बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों को व्यर्थ करना है। उदाहरण के लिए फसल उपजाने के लिए पानी की खपत या खाद का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। भोजन और खाद्यान्न की बर्बादी रोकने के लिए हमें अपने दर्शन और परम्पराओं के पुनर्चिंतन की जरूरत है। हमें अपनी आदतों को सुधारने की जरूरत है। धर्मगुरुओं एवं स्वयंसेवी संगठनों को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए। इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अभियान सोचें, खाएं और बचाएं भी एक अच्छी पहल है, जिसमें शामिल होकर की भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। हम सभी को मिलकर इसके लिए सामाजिक चेतना लानी होगी, तभी भोजन की बर्बादी रोकी जा सकती है। इसके अपने घर में फेंके जाने वाले खाने के बारे में आप जितना ज्यादा सोचेंगे, पृवी के अनमोल संसाधनों के संरक्षण की दिशा में आप उतना ही सकारात्मक परिवर्तन ला पाएंगे। खरीदने, पकाने और खाने जैसे छोटे-छोटे कदमों से ही आप पर्यावरण को बचाने में योगदान दे सकते हैं। अर्थात हमें पर्यावरण के वास्ते इस मसले पर ज्यादा संजीदगी और संवेदना से सोचना होगा। ●

E ZONE CARE

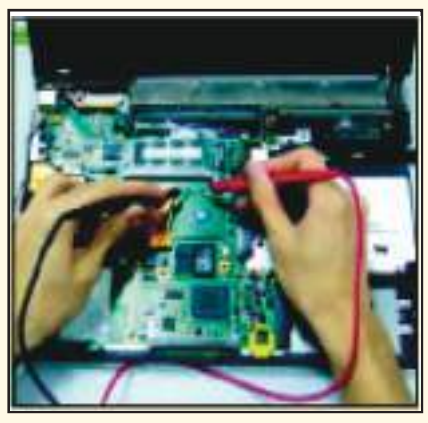



Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी )आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।